बिहार सरकार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

कतरन संख्या .....

तिथि 201

समाचार-पत्र का नाम ..... दैनिक भास्कर .....

प्रकाशन तिथि ..... 12/06/2020 .....

मंत्र

के

सह

बिहार चुनाव के लिए मोदी सरकार का ट्रम्प कार्ड

ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 से बढ़ा 12 लाख करने की तैयारी

मुकेश कौशिक | नई दिल्ली

केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दायरा बढ़ाने जा रही है। क्रीमी लेयर तय करने के लिए केंद्र सरकार सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तैयारी में है। अभी 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार ओबीसी के दायरे में आते हैं। ओबीसी की आय सीमा बढ़ाने को बिहार चुनाव के लिए रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। संसद की एक समिति ने क्रीमी लेयर की आय सीमा 15 लाख रुपए तक करने की सिफारिश की थी। इस पर विचार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने इसे घटाकर 12 लाख रुपए कर दिया। यह मामला कैबिनेट सचिवालय से होते हुए पीएमओ तक पहुंचं चुका है। इसे लेकर कैबिनेट नोट भी तैयार है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है।

मंत्रिसमूह में सहमति, आखिरी फैसला पीएमओ करेगा

- ओबीसी परिवार के सदस्य का वेतन कुल आय में जोड़ने पर तकनीकी पेच
- भाजपा नेताओं की राय- वेतन को आय में जोड़ने को विरोधी दल मुद्दा बना सकते हैं

फंसा पेच : सरकार और पीएसयू की नौकरियों के बीच दर्जे की समानता पर सहमति नहीं

आय सीमा बढ़ाने पर आम सहमति है। लेकिन इसमें ओबीसी परिवार के किसी सदस्य के सार्वजनिक उपक्रम या पब्लिक सेक्टर बैंक की नौकरी का वेतन शामिल करने का प्रस्ताव भी है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा में बेचैनी है। दलित राजनीति के अगुवा नेता मानते हैं कि इस वेतन को आय में जोड़ने को विरोधी दल मुद्दा बना सकते हैं। वेतन को ओबीसी परिवार के वेतन का हिस्सा बनाने को लेकर सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों के बीच दर्जे की समानता का मुद्दा भी जटिल है। मसलन, सरकार में कम वेतन के बावजूद कर्मचारी गजटेड के दायरे में आ जाते हैं, जबकि बैंकों में अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी उस स्तर के नहीं होते। यानी दोनों नौकरियों के बीच इक्वेलेंसी तय नहीं हुई है। इस वजह से वेतन को हाउसहोल्ड इनकम में जोड़ने को लेकर पेच है।

6/12/6

(एच० आर० श्रीनिवास)

बि०स०मु० (सूचना एवं जनसम्पर्क)-1-ऑफसेट-2,00,000-6.9.2018